भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1665

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

उद्योगों में कुशल श्रमबल की कमी

1665. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए कई योजनाएं चलाए जाने के बावजूद उद्योगों को कुशल श्रमबल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कौशल विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत सभी तीन कौशल विकास योजनाओं के विलय को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो कुशल श्रमबल की कमी को पूरा करने के लिए प्रस्तावित नई योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): नवीनतम अवधि श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) के अनुमानों के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्रमशः 4.1% और 30.6% है।

एमएसडीई की प्रमुख योजना **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)** का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में नौकरियों और कौशल क्षेत्र के तहत किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखा गया था और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख किया गया था, उन्हें उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): 2020 में आयोजित जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्वरोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सेदारी, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाना, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल का ध्यान स्वरोजगार पर है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): 2021 में आयोजित एनएपीएस के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई): एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्वरोजगार कर रहे हैं)।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना से युक्त केंद्रीय क्षेत्र योजना 'कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)' को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी। एसआईपी की निरंतरता और पुनर्गठन देश भर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुनर्गठित एसआईपी में किए गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल अंतर अध्ययन और पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के माध्यम से योगदान दिया गया है।

(ii) अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों के भीतर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) का एकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो;

(iii) शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई), केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों और उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के परस्पर उपयोग के माध्यम से मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना;

(iv) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, अंतर-मंत्रालयी अभिसरण को आगे बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे सभी क्षेत्रों में कौशल पहलों का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हो सके;

(v) शिक्षा से लेकर औपचारिक रोजगार तक के लिए शिक्षुता में बदलाव का समर्थन करता है, उद्योग-विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देता है और काम की दुनिया के वास्तविक जीवन के संपर्क के माध्यम से;

(vi) प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति शिक्षु अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह तक वृत्तिका भुगतान का 25% साझा करना;

(vii) एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों सहित मौजूदा विनिर्माण में शिक्षुता के अवसरों को प्रोत्साहित करता है;

(viii) जेएसएस स्कीम स्थानीय जरूरतों को पूरा करती है और उन्हें जीवन कौशल के साथ-साथ तकनीकी कौशल और उद्यमशीलता के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाती है, खासकर आकांक्षी जिलों और कठिन क्षेत्रों में।

(ix) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व-पंजीकरण, परामर्श, वित्तीय योगदान, लचीले प्रशिक्षण वितरण मॉडल को कवर करने वाला उम्मीदवार-केंद्रित दृष्टिकोण;

(x) बेहतर प्रशिक्षण जीवनचक्र प्रबंधन, आधार प्रमाणित नामांकन और बायोमेट्रिक उपस्थिति। प्रशिक्षण केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से और आकलन प्रमाणित आकलनकर्ताओं के माध्यम से ही किया जाएगा।

*****